सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को दिसम्बर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव (श्री ए.गिरिधर) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री मीरा स्वरूप, विशेष सचिव (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

    वरिष्ठ सलाहकार (सीएवंसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी एवं आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ संयुक्त सचिव(सीएवंसी)/ संयुक्त सचिव(आइपीपी)/(आईएसडी)/ सलाहकार (आईईआर)/ सलाहकार (बीसी)/ सलाहकार(प्रशा)/

सलाहकार(निवेश)/ सलाहकार(आर्थिक प्रभाग)/ सलाहकार(आईईआर)/ सलाहकार(आइपीपी)/सीएएए।

18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एवं सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल – 2021

सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः दिसंबर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहत्-आर्थिक अवलोकन

वित्त वर्ष की चालू तिमाही में भारत के आर्थिक सुधार में मजबूती आने की उम्मीद है, जैसा कि 2019 के इन्ही महीनों में उच्च आवृति संकेतकों (एचएफआई) का महामारी से पूर्व के अपने स्तर को पार करने से स्पष्ट है। प्रमुख बहुपक्षीय और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत से 2021 (वित्त वर्ष 21-22) में 8% -10% के बीच बढ़ने की अपेक्षा करती है और सरकार ऐसा करती भी है। आईएमएफ ने प्रमुख देशों में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, राज्यों में ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि आर्थिक सुधार के लिए एक जोखिम है। क्षेत्रवार वृद्धि दर **अनुबंध** में दी गई है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो अधिसूचनाएं जारी की गईं (i) 'बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध', 'अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रसीद' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करते हुए जारी करने हेतु सक्षम बनाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कारोबार करना और (ii) 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करना।

(ii) एक्जिम बैंक के माध्यम से किर्गिस्तान सरकार को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई।

(iii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) यूरोपीय निवेश बैंक से आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो का ऋण;

(ख) केएफडब्ल्यू से सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो का ऋण;

(ग) केएफडब्ल्यू से ऊर्जा सुधार कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए 140 मिलियन यूरो का ऋण और 2 मिलियन यूरो का अनुदान;

(घ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से उत्तराखंड एकीकृत और लचीला शहरी विकास परियोजना (किश्त 1) के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(ङ) एडीबी से तमिलनाडु परियोजना में शहरी गरीब क्षेत्र की परियोजना के लिए समावेशी, लचीला और सतत आवास के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(च) एडीबी से सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम (किश्त 1) परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(छ) एडीबी से असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए 112 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(ज) चेन्नई सिटी पार्टनरशिप के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण: विश्व बैंक से सतत शहरी सेवा कार्यक्रम;

(झ) विश्व बैंक से शिमला-हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति और सीवेज सेवा सुधार कार्यक्रम के लिए 160 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

(ञ) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 80 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए; तथा

(ट) विश्व बैंक से समावेशी सामाजिक सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल राज्य क्षमता निर्माण के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

3. दिसम्बर, 2021 माह के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं:

i. वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले निवेशकों के चयनित समूह के साथ माननीय प्रधान मंत्री की एक गोलमेज वार्ता आयोजित की गई।

ii. पहली जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की बैठक के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें माननीय वित्त मंत्री ने इंडोनेशिया की प्रेसीडेंसी के अंतर्गत जी-20 के वर्तमान विषय पर एक उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लिया: "एक साथ स्वस्थ हों, मजबूत हों"